



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 252]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 22, 2017/भाद्र 31, 1939

No. 252]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2017/BHADRA 31, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितंबर, 2017

(मामला संख्या O.I.16/2017)

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'एलॉय स्टील के स्ट्रेटलेन्थ बार और राड' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 6/10/2017-डीजीएडी— मै. जेएसडब्लू स्टील लिमिटेड, मै. जयसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मै. सनफ्लेग आयरन एंड स्टील कं. लिमिटेड, मै. ऊपा मार्टिन लि., मै. गेरडाउ स्टील इंडिया प्रा. लि. और मै. वर्धमान स्पेशल स्टील्स लि. (जिसे आगे याचिकाकर्ता कंपनियां या आवेदक भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एलॉय स्टील की स्ट्रेट लेन्थ बार और राड (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. और यतः प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जाँच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं, इसलिए प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जाँच की शुरूआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद स्ट्रेट लेंथ में एलॉय बार और राड हैं, चाहें होट रोल्ड, हाट ड्रान, कोल्ड ड्रान, कोल्ड एक्सट्रूडेड हो अथवा नहीं, पील्ड बार, सर्फेस मशीन्ड, पालिशड, ब्राइट बार, फोर्ज्ड। इस उत्पाद को विभिन्न क्रास सेक्शनों, आकारों और विमाओं में आपूर्ति किया जा सकता है, चाहें एनील्ड, सामान्यीकृत, टैम्पर्ड, ताप उपचारित हो अथवा नहीं। विचाराधीन उत्पाद को मापने की इकाई मी.टन है।

4. इस उत्पाद के अंतिम प्रयोग विभिन्न खंडों और क्षेत्रों में शामिल परंतु इन तक सीमित नहीं होते हैं जिनमें फोर्जिंग, आटोमोबाइल्स, आटो कलपुर्जे, क्रेक शाफ्ट, स्प्रिंग, गियर, फास्तेनर, ट्रांसमिशन शाफ्ट, सीमेंट संयंत्र, विद्युत संयंत्रों, टर्बाइनों, जलयान निर्माण, रेलवे, पूंजीगत सामान, मशीनरी, उपकरण, सामान्य इंजीनियरिंग, निर्माण मशीनरी और अनेक अन्य अंतिम प्रयोग अनुप्रयोगों में किया जाता है।

5. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की टैरिफ मद 7228 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। तथापि विचाराधीन उत्पाद के आयात टैरिफ शीर्ष 7214 और 7215 के अधीन भी देखे गये हैं। सीमाशुल्क वर्गीकृत केवल सांकेतिक हैं और वर्तमान जाँच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं हैं।

6. निम्नलिखित उत्पाद इस जाँच के दायरे से बाहर हैं :

- i. वाउंड काइलों में अनियमित रूप से बार और रॉड
- ii. उच्च स्पीड स्टील अर्थात् एलॉय स्टील जिसमें अन्य तत्वों के साथ या उनके बिना कम से कम तीन तत्व अर्थात् मोलिब्डेनम (एमओ), टंगस्टन (डब्लू) और वेनेडियम (वी) की मात्रा भार के अनुसार 7 प्रतिशत या उससे अधिक, 0.6 प्रतिशत से अधिक कार्बन और 3 प्रतिशत से 6 प्रतिशत क्रोमियम हो।
- iii. टूल और ड्राई स्टील : इस श्रेणी में निम्नलिखित तीन संयोगों में से किसी एक वाला स्टील होता है :

I. कार्बन $\geq 0.50\%$ क्रोमियम के साथ $\geq 1.0\%$ निम्नलिखित तत्वों में से कोई संयोजन: क. निकिल $\geq 1.0\%$ ख. मोलिब्डेनम $\geq 0.2\%$ ग. वेनेडियम $\geq 0.2\%$
II. कार्बन $\geq 0.30\%$ टंगस्टन के साथ यौगिक में $\geq 0.40\%$
III. कार्बन $\geq 0.30\%$ मैंगनीज के साथ $\geq 1.0\%$ और क्रोमियम $\geq 1.0\%$ निम्नलिखित तत्वों में से कोई संयोजन: क. निकिल $\geq 1.0\%$ ख. मोलिब्डेनम $\geq 0.2\%$ ग. वेनेडियम $\geq 0.2\%$

- iv. खोखले ड्रिल बार और राड
- v. क्रोम से इलेक्ट्रोप्लेटेड बार और रॉड।
- vi. कंक्रीट ढलाई के लिए प्रयुक्त रिब्स/गून्स/इंडेन्टेशन वाले रीइनफोर्समेंट बार।

vii. स्टेनलैस स्टील बार

समान वस्तु

7. आवेदकों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और भारत में पाटित की जा रही संबद्ध संबद्ध वस्तु समान हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसे मापदंडों के अनुसार तुलनीय विशेषताओं वाले हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। अतः प्राधिकारी वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के 'समान वस्तु' मानते हैं।

घरेलू उद्योग

8. यह आवेदन मै. जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, मै. जयसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मै. सनफ्लेग आयरन एंड स्टील कं. लिमिटेड, मै. ऊषा मार्टिन लि., मै. गेरडाउ स्टील इंडिया प्रा. लि. और मै. वर्धमान स्पेशल स्टील्स लि. द्वारा दायर किया गया है। रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार, उक्त सात उत्पादकों का उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा है और भारतीय उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक है। यह आवेदन तीन घरेलू उत्पादकों अर्थात् कल्याणी कार्पेंटर स्पेशल स्टील्स प्रा. लि., कल्याणी स्टील्स लि. और आर. एल. स्टील्स एंड एनर्जी लि. द्वारा समर्थित भी है। अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि समर्थक घरेलू उत्पादकों के साथ याचिकाकर्ता संबंधित नियमावली के नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग हैं और संबंधित नियमावली के नियम 5 (3) के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

शामिल देश

10. वर्तमान जाँच में शामिल देश चीन जन. गण. है।

सामान्य मूल्य

11. याचिकाकर्ताओं ने बताया है कि वे संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु की घरेलू बिक्री कीमतों को प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया है कि चीन जन. गण. में इस्पात उद्योग में भारी बाजार विकृतियाँ प्रचलित हैं। इसलिए संबद्ध देश में सामान्य मूल्य का अनुमान भारत में उत्पादन लागत के आधार पर घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्रियों की लागत, घरेलू उद्योग की सुविधाओं और परिवर्तन लागत पर विचार करते हुए और बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों जमा तर्कसंगत लाभ को विधिवत रूप से समायोजित करके लगाया गया है।

12. तथापि, प्रश्नावली का उत्तर देते हुए उत्पादक/निर्यातक उत्पादन लागत, सरकारी हस्तक्षेप, विनिमय दर परिवर्तन, दिवालिया और संपत्ति कानून आदि के संबंध में स्पष्ट कर सकते हैं और पर्याप्त सूचना प्रदान कर सकते हैं।

निर्यात कीमत

13. आवेदकों ने डीजीसीआईएंडएस के आयात आकड़ों से प्राप्त आयात सांख्यिकी के आधार पर चीन जन. गण से विचाराधीन उत्पाद के लिए निर्यात कीमत को निर्धारित किया है। निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़े, अंतरदेशीय भाड़े, समुद्री बीमा, प्रहस्तन प्रभार, बैंक प्रभार और संबद्ध देश में गैर-वापसी योग्य वैट के लिए समायोजन सहित कीमत संबंधी समायोजन किये गये हैं।

पाटन मार्जिन

14. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना द्वार स्तर पर निर्यात कीमत के साथ की गई है जो संबद्ध देश के संबंध में भारी पाटन मार्जिन दर्शाता है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार निर्यात कीमत से अधिक है, जिससे प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

15. पाटनरोधी जाँच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए भारी पाटन मार्जिन के पर्याप्त साक्ष्य हैं।

क्षति और कारणात्मक संबंध

16. आवेदकों ने दावा किया है कि उन्हें वास्तविक क्षति हुई है और उन्होंने समग्र रूप से और घरेलू उत्पादन और घरेलू मांग के संबंध में आयातों में वृद्धि के अनुसार संबद्ध देश से कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देश से पाटन के कारण घरेलू उद्योग की बिक्री, उत्पादन, क्षमता उपयोग, मालसूची, लाभों आदि में विकृति आई है।

17. आवेदकों ने कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री के साक्ष्य के अनुसार प्रतिकूल कीमत प्रभावों का भी दावा किया है। प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी जाँच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण आवेदकों को हो रही क्षति के पर्याप्त साक्ष्य हैं।

जांच अवधि (पीओआई)

18. वर्तमान जाँच के लिए जाँच अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017 तक की है। क्षति जाँच अवधि में अप्रैल 13 –मार्च 14, अप्रैल 14 –मार्च 15, अप्रैल 15 –मार्च 16 और जाँच अवधि शामिल होगी।

सूचना प्रस्तुत करना

19. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने तथा प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है:

20. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। सूचना/अनुरोध निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत किए जाएं :

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
वाणिज्य विभाग
चौथा तल ,जीवन तारा बिल्डिंग,
5 संसद मार्ग,
नई दिल्ली- 110001

21. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षों को उस सूचना का अगोपनीय अंश उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

समय-सीमा

22. वर्तमान जाँच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

23. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरुआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपाय जारी रखने की जरूरत अथवा अन्यथा के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। सूचना मूल प्रति और साफ्ट प्रति दोनों में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

24. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए उसके किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा करने के मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा:-

(क). गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और

(ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि)।

25. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों पाठों की हार्ड कॉपियों के साथ साफ्ट कॉपियां प्रत्येक में दो (2) सैट में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

26. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

27. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

28. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

29. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

30. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

31. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

32. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd September, 2017

Case No. O.I.-16/2017**Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Straight Length Bars & Rods of Alloy Steel” originating in or exported from China PR.**

F. No.6/10/2017-DGAD.— M/s. JSW Steel Limited, M/s. Jayaswal Neco Industries Limited, M/s. Sunflag Iron & Steel Co. Limited, M/s. Usha Martin Limited, M/s. Gerdau Steel India Private Limited and M/s. Vardhman Special Steels Limited (hereinafter referred to as “petitioner companies” or “the applicants”) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) have submitted an application for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty on the imports of Straight Length Bars & Rods of Alloy Steel (hereinafter referred to as the subject goods or the Product Under Consideration), originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the “subject country”).

2. And whereas, the Authority prima facie finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation; the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the ‘injury’ to the domestic industry.

A. Product under consideration

3. The product under consideration for the purpose of present investigation is “Alloy bars and rods in straight length, whether or not hot rolled, hot drawn, cold drawn, cold extruded, peeled bar, surface machined, polished, bright bar, forged.” The product may be supplied in various cross sections, shapes and dimensions whether or not annealed, normalized, tempered, heat treated. The unit of measurement for the product under consideration is taken as MT.
4. The product may find end use application across various segments and sectors including but not limited to forging, automobiles, auto components, crank shaft, springs, gears, fasteners, transmission shaft, cement plants, power plants, turbines, ship-building, railways, capital goods, machinery, equipment, general engineering, construction machinery, and many more end use applications.
5. The product under consideration is classified under Tariff item 7228 of the Custom Tariff Act, 1975. However, imports of product under consideration has also been observed under tariff headings 7214 and 7215. The customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.
6. The following products are excluded from the scope of this investigation:
 - i. Bars and rods in irregularly wound coils.
 - ii. High Speed Steel i.e. alloy steels containing, with or without other elements, at least two of the three elements namely Molybdenum (Mo), Tungsten (W) and Vanadium (V) with a combined content by weight of 7% or more, 0.6% or more of Carbon and 3% to 6% of Chromium.

- iii. Tool and Die Steel: This category covers steel having either of the following three combinations:

1.	<p>a. Carbon $\geq 0.50\%$ along with Chromium $\geq 1.0\%$ in combination of any of the following elements:</p> <p>b. Nickel $\geq 1.0\%$</p> <p>c. Molybdenum $\geq 0.2\%$</p> <p>d. Vanadium $\geq 0.2\%$</p>
2.	Carbon $\geq 0.30\%$ in combination with Tungsten $\geq 0.40\%$
3.	<p>a. Carbon $\geq 0.30\%$ along with Manganese $\geq 1.0\%$ and Chromium $\geq 1.0\%$ in combination of any of the following elements:</p> <p>b. Nickel $\geq 1.0\%$</p> <p>c. Molybdenum $\geq 0.2\%$</p> <p>d. Vanadium $\geq 0.2\%$</p>

- iv. Hollow drill bars and rods.
- v. Bars and rods electroplated with chrome.
- vi. Reinforcement Bars having ribs / grooves / indentations, used for concrete reinforcement.
- vii. Stainless Steel bars.

B. Like Article

7. The applicants have claimed that the subject goods being produced by the domestic industry are similar to the subject goods being dumped into India. The applicants have claimed that PUC produced by the applicants and imported from the subject country are having comparable characteristics in terms of parameters such as physical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicants in India are being treated as 'like article' to the subject goods being imported from the subject country.

C. Domestic Industry & Standing

8. The Application has been filed by M/s. JSW Steel Limited, M/s. Jayaswal Neco Industries Limited, M/s. Sunflag Iron & Steel Co. Limited, M/s. Usha Martin Limited, M/s. Gerdau Steel India Private Limited and M/s. Vardhman Special Steels Limited. As per the information available on record, the production of the aforesaid seven producer's accounts for a major proportion of the total domestic production and is more than 50% of Indian production. The Application has also been supported by three domestic producers, namely, Kalyani Carpenter Special Steels Private Limited, Kalyani Steels Limited and R.L. Steels and Energy Limited.
9. The Authority holds that the petitioner along with supporting domestic producers constitutes an eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b) and satisfies the criteria of standing also in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

D. Subject Country

10. The country involved in the present investigation is China PR.

E. Normal Value

11. The petitioners have submitted that they have not been able to collect domestic selling prices of the subject goods in the subject country. The petitioners also claim that there is significant distortions prevailing in Steel Industry in China PR. Therefore, the Normal Value in the subject country has been estimated on the basis of cost of production in India; taking into account cost of raw material of domestic industry, cost of utilities and conversion cost of domestic industry, duly adjusted on account of selling, general & administration expenses, plus reasonable profit.
12. However, while submitting the questionnaire response producers/exporters may have to demonstrate prevalence of market condition related to manufacture, production and sales of subject good in the domestic market and in export to India and other countries. For this purpose, the producer/exporter, may clarify and provide sufficient information on the following:
 - a) Decision with regard to price, cost, input including raw material, cost of technology and labour, output, sales and investment are without significant state interference and whether cost of major inputs substantially reflect market value.
 - b) Production costs and financial situation does not suffer for any distortion.
 - c) The producer/exporter are subject to bankruptcy and property law which guarantees legal certainty and stability for the operation of the firms.
 - d) Exchange rate conversions are carried out at the market rate.

F. Export Price

13. The applicants have determined the export price for the product under consideration for China PR based on the import statistics obtained from DGCI&S imports data. Price adjustments have been made on account of Ocean Freight, Inland Freight, Ocean Insurance, Handling Charges, Bank Charges and Non-Refundable VAT for the subject country.

G. Dumping Margin

14. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which shows significant dumping margin in respect of the subject country. There is sufficient prima facie evidence that the normal values of the subject goods in the subject country are significantly higher than the ex-factory export price, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country.
15. There is sufficient evidence of the significant dumping margins to justify initiation of antidumping investigation.

H. Injury and Causal Link

16. The applicants have claimed that they have suffered material injury and have furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping from the subject country in terms of increase in imports in absolute terms and in relation to domestic production and domestic demand. The dumping from the subject country has resulted in deterioration of sales, production, capacity utilization, inventories, profits, etc. of the domestic industry.
17. The applicants have also claimed adverse price effects as evidenced by price undercutting and price underselling. The Authority considers that there is sufficient evidence of 'injury' being suffered by the applicants caused by dumped imports of the subject goods from the subject country to justify initiation of an antidumping investigation.

I. Period of Investigation

18. The period of investigation (POI) for the present investigation is from April 2016 to March 2017. The injury investigation period will, however, cover the periods April 2013-March 2014, April 2014-March 2015, April 2015-March 2016 and the POI.

J. Submission of information

19. The known exporters in the subject country and its Government through its Embassy in India, importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below.
20. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time limit set out below. The information/submissions may be submitted to:

**The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce
Government of India
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5, Parliament Street,
New Delhi-110001**

21. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

K. Time Limit

22. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of the publication of initiation notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.
23. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within forty days (40 days) from the date of the publication of initiation notification. The information must be submitted in hard copies as well as in soft copies.

L. Submission of information on confidential basis

24. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:
 - i. one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
 - ii. The other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).
25. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in two (2) sets of each.
26. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
27. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the

substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

28. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
29. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
30. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information

L. Inspection of Public File

31. In terms of Rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

M. Non-cooperation

32. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority